

# सुबह से शाम

S.S. Media  
Group

तक की खबरें  
मूल्य - 2₹

\* वर्ष: 19 \* अंक: 18 \* मुंबई, रविवार, 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 \* संपादक:- एस.के.तिवारी \* पेज: 4

Email Id - ssnews2008@gmail.com

www.subahsesham.com

## ज्ञानेश कुमार जाएंगे, मोदी सरकार भी जाएगी, फिर लोकतंत्र की मरम्मत होगी : राहुल गांधी



### संवाददाता

**नई दिल्ली।** मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कॉंग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के आह्वान के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसी बीच काँग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार जाएंगे, मोदी सरकार भी जाएगी और उसके बाद लोकतंत्र की मरम्मत का काम शुरू होगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए

लिखा, “ज्ञानेश कुमार जाएंगे, यह सरकार जाएगी। फिर लोकतंत्र की मरम्मत शुरू होगी।” उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ संसद के सेंट्रल हॉल में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सांसदों को संबोधित करते हुए दिए गए भाषण का वीडियो भी साझा किया। इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी अधिक गंभीर समस्या मौजूदा सरकार है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार को बदलना आवश्यक है। राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों से जारी विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों ने सरकार की नींव हिला दी है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इसी प्रकार दबाव बनाए रखता है, तो सरकार गिर

**मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत कई नेताओं को हिरासत में लेने का दावा, भाजपा ने कहा— देश संसद से चलेगा, सड़क से नहीं**



सकती है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, “अगर हम पिछले तीन-चार दिनों की तरह ही दबाव बनाए रखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि यह सरकार गिर जाएगी।” दूसरी ओर, सीजेपी के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके चलते जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात किए गए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके चलते जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात किए गए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके चलते जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात किए गए।

जाने और कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होने का भी दावा किया गया है। हालांकि, इन प्रतिबंधों के संबंध में संबंधित अधिकारियों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। प्रदर्शन से पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली हवाई अड्डे पर पुलिस ने हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की जानकारी दी गई। केरल भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन और सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास को भी हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया। (शेष पेज 2 पर)

## विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें

अगर आप अपने विशेष अवसरों को खास बनाना चाहते हैं या महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यापक जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो साप्ताहिक 'सुबह से शाम तक की खबरें' आपके लिए सही मंच है। चाहे जन्मदिन कीबधाई हो, शादी की सालगिरह, गुमशुदगी की सूचना, कानूनीनोटिस या कोई अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विज्ञापन, हम आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करेंगे। आपके विज्ञापन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इसे और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी।  
ईमेल: Email Id - ssnews2008@gmail.com  
या वाट्सएप नं. 8898330400

## हर बच्चे को परिवार का अधिकार: मंत्री आदिती तटकरे

### संवाददाता

**मुंबई।** असुरक्षित बच्चों को संस्थागत देखभाल में रखने के बजाय परिवार और समुदाय आधारित विकल्प उपलब्ध कराने पर महाराष्ट्र सरकार विशेष जोर दे रही है। ‘हर बच्चे को परिवार का अधिकार है’ के सिद्धांत के तहत राज्य में बाल संरक्षण व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने कहा कि फोस्टर केयर, गोद लेने की प्रक्रिया और आप्टर केयर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के साथ केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) पोर्टल और मिशन वात्सल्य के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए तटकरे ने राज्य में बाल संरक्षण के लिए लागू विभिन्न योजनाओं और पहलों की जानकारी दी। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री भी शामिल हुए। तटकरे ने बताया कि महाराष्ट्र में असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा के लिए पालक देखभाल (फोस्टर केयर), दत्तक ग्रहण और पश्चात देखभाल (आप्टर केयर) को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि जहां संभव हो, बच्चों को संस्थानों के बजाय परिवार या समुदाय आधारित सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

**1% आरक्षण से 1,060 अनाथ युवाओं को सरकारी नौकरी**  
महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए सरकारी

**फोस्टर केयर, गोद लेने और आप्टर केयर व्यवस्था होगी मजबूत एक प्रतिशत आरक्षण से 1,060 अनाथ युवाओं को मिली सरकारी नौकरी**



नौकरियों में लागू एक प्रतिशत समांतर आरक्षण से सितंबर 2026 तक कुल 1,060 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। इनमें वर्ग-1 के 4, वर्ग-2 के 68, वर्ग-3 के 974 और वर्ग-4 के 14 उम्मीदवार शामिल हैं। राज्य सरकार सितंबर 2026 तक लगभग 12,443 अनाथ प्रमाणपत्र भी जारी कर चुकी है। इन प्रमाणपत्रों के आधार पर पात्र बच्चों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

### उच्च और तकनीकी शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार

तटकरे ने बताया कि अनाथ बच्चों की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा परीक्षा शुल्क का पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है। इस संबंध में 17 जुलाई 2025 को लिए गए निर्णय का अब तक 99 से

अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। इसके अलावा क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना के तहत राज्य के करीब दो लाख बच्चों को प्रतिमाह 2,250 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि बाल संरक्षण केवल बच्चों को आश्रय उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होना चाहिए। बच्चों को सुरक्षित पारिवारिक वातावरण, शिक्षा, आर्थिक सहायता और आगे चलकर आत्मनिर्भर बनाने के अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने CARA पोर्टल और मिशन वात्सल्य के बीच बेहतर समन्वय के साथ प्रत्येक बच्चे के मामले को नियमित निगरानी और प्रभावी फॉलोअप पर जोर दिया, ताकि जरूरतमंद बच्चों को समय पर सही देखभाल और पुनर्वास का अवसर मिल सके।

## भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये पहुंचा, 2029 तक 50 हजार करोड़ का लक्ष्य: राजनाथ सिंह

### संवाददाता

**नई दिल्ली।** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा उपकरणों के बड़े आयातक देश से आधुनिक सैन्य उपकरणों के विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत से अधिक है। इस वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात को 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स (SIDM) के आठवें वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विभिन्न संगठनों को SIDM चैंपियन पुरस्कार 2026 प्रदान किए। कार्यक्रम में कुल 15 पुरस्कार दिए गए। इन पुरस्कारों के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास, उत्पाद नवाचार, डिजाइन, आयात के विकल्प तैयार करने, डिजिटल निर्माण में उत्कृष्ट प्रदर्शन और रक्षा निर्यात के क्षेत्र में संगठनों की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। राजनाथ सिंह ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते

हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए स्वदेशी उद्योगों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।  
**राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी रक्षा तकनीक जरूरी**  
इस वर्ष के वार्षिक सत्र की विषयवस्तु ‘संग्रभू क्षमताएं, विवादित सीमाएं: उथल-पुथल के दौर में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना’ थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि कोई देश अपनी रक्षा सेनाओं के लिए आवश्यक तकनीक और उपकरणों का डिजाइन, विकास तथा निर्माण स्वयं किस हद तक कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास प्रतिभाशाली मानव संसाधन, युवा कार्यबल, मजबूत औद्योगिक क्षमताएं और अनुकूल नीतिगत समर्थन उपलब्ध है। इन क्षमताओं के बल पर भारत दुनिया के प्रमुख रक्षा विनिर्माण देशों में स्थान बना सकता है।  
**रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत करने पर जोर**  
राजनाथ सिंह ने देश के कुल रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निजी क्षेत्र की मौजूदा लगभग 24

**रक्षा मंत्री ने SIDM के वार्षिक सत्र में दिए 15 चैंपियन पुरस्कार, रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का आह्वान**



प्रतिशत हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का अपना पूर्व आह्वान दोहराया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों का योगदान उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। अब रक्षा उद्योग को अनुसंधान, तकनीकी विकास और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। रक्षा मंत्री ने उद्योग जगत को आवश्यक देशों में स्थान बना सकता है।  
**आधुनिक युद्ध में ड्रोन, मिसाइल और नई तकनीकों की बढ़ती भूमिका**  
युद्ध के बदलते स्वरूप का उल्लेख करते

हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक सैन्य अभियानों में ड्रोन, मिसाइल, वायु रक्षा प्रणालियों तथा तेजी से विकसित हो रही सॉफ्टवेयर और संचार तकनीकों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने रक्षा उपकरण निर्माताओं से अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले खर्च को केवल मजबूत करने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया। (शेष पेज 2 पर)

## महाराष्ट्र में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार टेली-मानस हेल्पलाइन पर 3.27 लाख से अधिक कॉल

### संवाददाता

**मुंबई।** महाराष्ट्र में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों को समय पर परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। टेली-मानस हेल्पलाइन, मनशक्ति क्लिनिक, स्मृतिदोष क्लिनिक और मनोसामाजिक पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। यह जानकारी राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने दी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (10 अक्टूबर) के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आंबेडकर ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। लोगों को अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बातचीत करने, समय पर सहायता लेने और जरूरतमंद व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस वर्ष राज्य में ‘मनजागृति’ और ‘मनसंवाद’ के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष की वैश्विक संकल्पना बनाने में सहायता मिलेगी। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया। (शेष पेज 2 पर)

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर ‘मनजागृति’ और ‘मनसंवाद’ अभियान से जागरूकता पर जोर, स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर बोले— समय पर उपचार और परामर्श मिलना जरूरी



है। ऐसे व्यक्तियों के अनुभवों को स्वास्थ्य सेवाओं और निर्णय प्रक्रिया में भी महत्व दिए जाने की आवश्यकता बताई गई है।  
**टेली-मानस हेल्पलाइन पर 3.27 लाख से अधिक कॉल**  
मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 चौबीसों घंटे संचालित की जा रही है। महाराष्ट्र में वर्ष 2022-23 से अप्रैल 2026 तक इस हेल्पलाइन पर 3 लाख 27 हजार से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं। इस सेवा के माध्यम से नागरिक घर बैठे फोन पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन

और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।  
**प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मानसिक स्वास्थ्य उपचार**  
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों के घरों के नजदीक उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर मनशक्ति क्लिनिक के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। इन केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान, परामर्श, उपचार और आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के लिए मरीजों को रेफर करने की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी (शेष पेज 2 पर)

## जीएसटी में बड़े सुधारों की सिफारिश: गिरफ्तारी प्रावधान हटाने, अभियोजन सीमा 5 करोड़ करने का प्रस्ताव

### संवाददाता

**नई दिल्ली।** केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में कारोबारियों और करदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की गई। परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान हटाने, आपराधिक अभियोजन की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने और सामान्य अधिकतम जुर्माना 25 हजार से घटाकर 10 हजार करने की सिफारिश की है। बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), विवाद समाधान और ई-कॉमर्स कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया गया। परिषद ने सुझाव दिया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और स्वचालित बनाई जाए। कुछ श्रेणियों में रजिस्ट्रेशन और उसमें संशोधन अधिकारी के हस्तक्षेप के बिना

पोर्टल के माध्यम से स्वतः स्वीकार किए जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया को भी सिस्टम आधारित और तेज बनाने की सिफारिश की गई है।  
**छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं को राहत**  
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई है। ऐसे विक्रेता संबंधित राज्य में ई-कॉमर्स कंपनी के गोदाम को अपना प्रमुख व्यावसायिक स्थान घोषित कर सकेंगे, जिससे उन्हें हर राज्य में अलग कार्यालय स्थापित करने की जरूरत कम होगी।  
**रिफंड की 90% राशि जल्द मिलने का रास्ता**  
परिषद ने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को भी अधिक स्वचालित बनाने का प्रस्ताव रखा है। शून्य-दर आपूर्ति और इन्वेंट्री में इयूटी स्ट्रक्चर से जुड़े पात्र मामलों में जेखिम मूल्यांकन के आधार पर दावे

की 90 प्रतिशत राशि अस्थायी तौर पर स्वतः मंजूर करने की सिफारिश की गई है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त राशि के रिफंड को भी बिना अधिकारी के हस्तक्षेप के सिस्टम के माध्यम से मंजूर करने का प्रस्ताव है। रिफंड आवेदन की पावती या कमी संबंधी मेमो जारी करने की समयसीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने की सिफारिश की गई है।  
**ITC का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव**  
परिषद ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को अधिक सहज बनाने के लिए कई प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की है। इसमें आउटडोर कैटरिंग, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, टेलीकॉम टावर, कुछ पाइपलाइन, मुफ्त नमूने और निर्धारित परिस्थितियों में नष्ट या समाप्त की गई वस्तुओं पर ITC से जुड़े प्रतिबंधों में राहत का प्रस्ताव शामिल है। इन्वेंट्री इयूटी स्ट्रक्चर और शून्य-दर आपूर्ति

से जुड़े मामलों में इनपुट सेवाओं तथा पूंजीगत वस्तुओं पर जमा ITC के रिफंड की पात्रता भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।  
**छोटी कर मांगों पर नोटिस नहीं:**  
जीएसटी परिषद ने 10 हजार से कम कर मांग वाले मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी न करने की सिफारिश की है। साथ ही धोखाधड़ी से जुड़े नहीं होने वाले मामलों में निर्धारित समय के भीतर कर और ब्याज जमा करने पर जुर्माना कम करने का प्रस्ताव है। सीजीएसटी कानून की धारा 125 के तहत सामान्य अधिकतम जुर्माना भी 25 हजार से घटाकर 10 हजार करने की सिफारिश की गई है। सेवाओं के निर्यात को बढ़ावापरिषद ने भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए निर्यात संबंधी जीएसटी नियमों को सरल बनाने के उपाय सुझाए हैं। इससे विदेशी शाखाओं या कार्यालयों को दी जाने वाली सेवाओं पर रिफंड

**सामान्य जुर्माना 25 हजार से घटाकर 10 हजार करने की सिफारिश, रिफंड, ITC और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी होगी आसान**



और जीएसटी लाभ प्राप्त करना आसान हो सकेगा। राज्यों के बीच माल परिवहन होगा आसानपरिषद ने राज्यों के बीच माल की आवाजाही को सरल बनाने और वाहनों को रोककर जांच करने के लिए भी समान मानक बनाने की सिफारिश की है। गोपनीय

या अधिकृत सूचना के आधार पर ही वाहनों को रोककर माल की जांच करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसके अलावा 5 करोड़ तक वार्षिक कारोबार वाले और सीधे उपभोक्ताओं से कारोबार करने वाले छोटे व्यवसायों के लिए एक वैकल्पिक

योजना को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। परिषद का कहना है कि इन सुधारों से कारोबारियों का अनुपालन बोझ कम होगा, विभागीय अधिकारियों से सीधा संपर्क घटेगा, रिफंड तेजी से मिलेगा और व्यवसायों की कार्यशील पूंजी की स्थिति बेहतर होगी।

## संपादकीय



## लोकतंत्र में आंदोलन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता

**लो**कतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल चुनाव कराने या सरकार बनाने में नहीं, बल्कि नागरिकों को सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछने का अधिकार देने में भी निहित है। जब किसी संस्था के निर्णयों को लेकर जनता के एक वर्ग में असंतोष पैदा होता है, तो शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन उस असंतोष को सामने लाने का महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक माध्यम बनता है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर जारी राजनीतिक विवाद को भी इसी व्यापक लोकतांत्रिक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे सवालों को केवल राजनीतिक हार-जीत की प्रतिक्रिया मानकर खारिज करना उचित नहीं होगा। हालांकि विपक्ष के आरोपों की सत्यता का निर्धारण तथ्यों, दस्तावेजों और संवैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पर ही होना चाहिए। मतदाता सूची में किसी पात्र नागरिक का नाम छूटने या गलत तरीके से हटाए जाने की आशंका अपने आप में गंभीर विषय है। मतदान का अधिकार लोकतांत्रिक भागीदारी का आधार है और उसकी सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक चिंता स्वाभाविक है। इतिहास बताता है कि शांतिपूर्ण जनआंदोलनों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों तक, जनता की संगठित आवाज ने शासन व्यवस्था को अपनी नीतियों और निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए सड़क पर उतरकर असहमति व्यक्त करना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति का एक वैध रूप है। एसआईआर जैसी व्यापक प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करना भी लोकतांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा है। चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और आपत्तियों के निस्तारण के लिए कौन-से मानदंड अपनाए जा रहे हैं। जिन नागरिकों को दस्तावेजों या पुरानी मतदाता सूची से संबंधित जानकारी जुटाने में कठिनाई हो रही है, उनके लिए सरल और प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त यही है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर मिले। हाल के घटनाक्रम ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता और प्रशासनिक प्रतिबंधों के बीच तनाव को भी सामने रखा है। दिल्ली में विपक्षी नेताओं, छात्रों और नागरिक समूहों के प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए जाने तथा कई स्थानों पर आवाजाही प्रतीबंधित किए जाने की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जरूरत बताई है, जबकि प्रदर्शनकारियों ने इन कदमों को असहमति व्यक्त करने के अधिकार पर अंकुश बताया है। आम जनता को होने वाली परेशानी निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन हर यातायात अवरोध या असुविधा के लिए केवल आंदोलनकारियों को जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं होगा। कई बार वैरिकेडिंग, परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी जनजीवन को प्रभावित करती है। इसलिए प्रशासनिक कदमों की आवश्यकता और उनके अनुपात की भी समीक्षा होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण सभा के अधिकार के साथ सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरे नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता को स्वीकार किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग राजनीतिक रूप से उठाई जा रही है, लेकिन उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया सिंधिधान के अनुच्छेद 324(5) के अधीन है। इसी प्रकार चुनाव आयोग के निर्णयों पर सवाल उठाना और उनके समर्थन में तर्क देना, दोनों लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हैं। जरूरी यह है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और आयोग जनता के सामने तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण रखे। लोकतंत्र की मजबूती का अर्थ केवल संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना नहीं, बल्कि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। शांतिपूर्ण आंदोलन, न्यायिक समीक्षा और सार्वजनिक बहस इस जवाबदेही के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। असहमति को सुनने, प्रदर्शन के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराने और मतदाताओं की वास्तविक शिकायतों का समाधान करने से ही नागरिकों का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा मजबूत हो सकता है।

## जयप्रकाश और संपूर्ण क्रांति: लोकतंत्र के मूल्यों की पुनर्स्थापना का आह्वान

रविशंकर कुमार चौधरी

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 5 जून, 1974 एक ऐसा दिन है जो व्यापक सामाजिक और वैचारिक जागरण का प्रतीक बन गया। इसी दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। यह आंदोलन केवल किसी सरकार के खिलाफ विरोध का स्वर नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को जगाने वाला वह प्रयास था जिसने व्यवस्था परिवर्तन की मांग करते हुए राष्ट्र को पुनर्नर्चना की दिशा में सोचने को विवश किया। संपूर्ण क्रांति' का अर्थ था - राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन से आगे जाकर समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और नैतिक जीवन के हर स्तर पर बदलाव की आवश्यकता को स्वीकार करना। 1970 के दशक में भारत गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और शासन व्यवस्था की विफलताओं से जूझ रहा था। युवाओं और छात्रों में असंतोष गहराता जा रहा था, विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में जहाँ शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचे चरमराने लगे थे। इन्हीं परिस्थितियों में छात्रों द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों को व्यापक दिशा देने के लिए जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने न केवल आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया, बल्कि इसे वैचारिक स्वरूप देते हुए संपूर्ण क्रांति का नाम दिया, जिसका उद्देश्य था- नए भारत की संरचना। जेपी का मानना था कि लोकतंत्र केवल चुनावों और सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जनभागीदारी, पारदर्शिता, सेवा और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए।



उन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानते हुए उसमें युवाओं की भागीदारी को आवश्यक बताया। उनका विश्वास था कि यदि व्यवस्था शोषणकारी और भ्रष्ट हो चुकी है तो उसके ढांचे में बदलाव आवश्यक है। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक - इन सात क्षेत्रों में समांतर क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया। धीरे-धीरे जेपी का नेतृत्व संपूर्ण राष्ट्र में लोकतांत्रिक चेतना का वाहक बन गया। जब इस आंदोलन की तीव्रता ने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की नींव को चुना। 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। नागरिक अधिकारों का हनन, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी जैसे कठोर कदम उठाए गए। किंतु संपूर्ण क्रांति की चेतना को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सका। जनता के भीतर जाग चुकी लोकतांत्रिक चेतना ने 1977 के आम चुनाव में सत्ता परिवर्तन के रूप में ऐतिहासिक परिणाम दिए और पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। कहा

### पेज 1 का शेष ज्ञानेश कुमार जाएंगे...

ब्रिटास ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती रही, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिल्ली के साउथ एवेन्यू क्षेत्र से हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेंक ओ ब्रायन, डोला सेन और अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ममता बनर्जी की कथित हिरासत का वीडियो साझा करते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। पार्टी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “दिल्ली पुलिस, आपकी हिम्मत कैसे हुई?” तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लेना कब से सामान्य बात हो गई। पार्टी ने कहा कि यदि शांतिपूर्ण विरोध का जवाब बातचीत के बजाय गिरफ्तारियों से दिया जाता है, तो इससे लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वहीं, विरोध प्रदर्शनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष और सीजेपी पर तीखा हमला बोला। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में कहा कि देश संसद से चलेगा, सड़क से नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन अराजकता का विरोध करती है। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि सीजेपी आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि संगठन के रूप में काम कर रही है और उसके प्रदर्शन के कारण दिल्ली की आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों पर भी सवाल उठाए और उन पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा नेता ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया का बचाव करते हुए इसे संवैधानिक बताया। प्रसाद ने दावा किया कि नौ से अधिक देशों में भी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोई व्यक्ति भारत

## शारदेय नवरात्र: जन-मन में शक्ति की अलख

हेमेन्द्र क्षीरसागर

अश्विन मास के आगमन के साथ ही शारदेय नवरात्र का पावन पर्व पूरे देश में आत्मीयता, आस्था और सांस्कृतिक ऊर्जा का संचार करने लगता है। यह केवल नौ दिनों के धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित पर्व नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों, नैतिक मूल्यों और नारी शक्ति के सम्मान की सामूहिक अभिव्यक्ति है। जन-मन में शक्ति की जीती-जागती अलख है। स्तुत्य, सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर विजय। पौराणिक कथाओं में माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध वास्तव में हमारे भीतर छिपी नकारात्मकताओं। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को समाप्त करने का आह्वान है। इस पर्व की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि यह ईश्वर को 'माता' के रूप में पूजने की परंपरा सिखाता है। जहाँ शक्ति का आधार करुणा और रक्षण है। अतुल्य, नवरात्र का असली सौंदर्य भारत के गाँवों और जनजातों अंचलों में झलकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्र नई फसल की आमद और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का समय है। घटस्थापना में बौए जाने वाले 'ज्वारे' सोधे तौर पर कृषि और समृद्धि से जुड़े हैं। जनजातीय बहुल क्षेत्रों जैसे मध्य भारत के गोंड, बैगा, बस्तर या बालाघाट का प्रसिद्ध दशहरा में माँ दुर्गा को बूढ़ी माई,



खरमाई या ग्राम देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संकल्प के साथ पारंपरिक वाद्ययंत्रों और लोकनृत्यों के बीच माँ की आराधना होती है। जो हमारी सबसे प्राचीन और अखंड आध्यात्मिक परंपरा है। यथेष्ट, पंडालों में सजती माँ की प्रतिमाएँ, जरा, भजन, रामलीला, ड्रामा, डंडियार, डोंडिया-गरबा का उल्लास और जगृाते केवल मनोरंजन नहीं हैं। ये समाज को ऊँच-नीच, भेद-भाव से ऊपर उठाकर एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। यह जन-जन में जागृति लाने का नशा मुक्ति, बाल देखभाल, शिक्षा व नारी-सुरक्षा का वातावरण बनाने का संकल्प लें। जय मां जगदम्बे!

का नागरिक नहीं है, तो उसका नाम मतदाता सूची में कैसे शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। भाजपा सांसद ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल बनाने का आरोप भी लगाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी प्रदर्शनों ने राजधानी में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। विपक्षी दल पुलिस कार्रवाई को शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं, जबकि भाजपा प्रदर्शन के तरीके और उससे आम नागरिकों को होने वाली परेशानी का मुद्दा उठा रही है।

### भारत का रक्षा निर्यात...

उन्होंने कहा कि किसी आपात आवश्यकता या सैन्य अभियान के दौरान घरेलू रक्षा उत्पादन इकाइयों की क्षमता को तेजी से बढ़ाने की व्यवस्था होना आवश्यक है। उन्होंने रक्षा उद्योग से विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने और बदलती सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप कम समय में प्रभावी समाधान विकसित करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत करने के लिए केवल रक्षा उपकरणों का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आवश्यक तकनीकों, डिजाइन और उत्पादन प्रक्रियाओं पर भी देश का नियंत्रण होना चाहिए।

### महाराष्ट्र में मानसिक...

समस्याओं का सामना कर रहे व्यक्तियों के पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

स्मृतिदोष क्लिनिक से हर साल 45 हजार से

अधिक नागरिकों को लाभ

बढ़ती उम्र के साथ होने वाली स्मरणशक्ति संबंधी समस्याओं की पहचान और उपचार के लिए राज्य में विशेष स्मृतिदोष क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। इन क्लिनिकों की बाढ़ रोगी सेवाओं से हर वर्ष लगभग 45 हजार से अधिक नागरिक लाभान्वित होते हैं। विशेष रूप से स्मरणशक्ति संबंधी समस्याओं से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों को चिकित्सकीय मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

मन और आचरण को शुद्धता है। नवरात्र के दौरान किया जाने वाला कन्या पूजन समाज को सीधा संदेश देता है कि नारी का सम्मान ही माँ की सच्ची आराधना है। जिस घर या समाज में बेटी और स्त्री का सम्मान नहीं, वहाँ माँ दुर्गा की कृपा संभव नहीं। अभिभूत, चाहे गुजरात का गरबा हो, बंगाल की दुर्गा पूजा, उत्तर भारत की रामलीला हो दक्षिण भारत का बोम्पू गोलू या ग्रामीण चौपालों के लोक-अनुष्ठान। यह शारदेय नवरात्र भारत की 'विविधता में एकता' को जीवंत करता है। नवरात्र पर्व हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित करता है। जिससे नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है। आइए, इस शारदेय नवरात्र पर न केवल पूजा-पंडालों में माँ का स्वागत करें। अपने भीतर की बुराइयों का अंत करने और समाज में सौहार्द, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, बाल देखभाल, शिक्षा व नारी-सुरक्षा का वातावरण बनाने का संकल्प लें। जय मां जगदम्बे!

### वसई-विरार शहर महानगरपालिका

प्रभाग समिती (ई) नालासोपारा (पश्चिम)

मुख्य कार्यालय विरार

दुरध्वनी क्र. १२२५० - २४०२१७९ / २४०२५६३

जावक. क्र.: व.वि.श.म./क.वि./२१३१/२०२६-२७

दिनांक:- ०७/१०/२०२६

जाहिर नोटीस

महाराष्ट्र मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४६९ अन्वये जाहिर नोटीस खालील मालमत्तेच्या हस्तांतरण संबंधाने वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ई) कार्यालय नालासोपारा येथे प्राप्त झालेल्या मालमत्ता धारकांच्या प्रकरणपरत्वे नोटीसीनुसार सदर हस्तांतरण संदर्भाने कोणत्याही हितसंबंधाने हरकत अगर आक्षेप असल्यास ही नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत हितसंबंधाच्या लेखी पुराव्यासह वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती (ई) कार्यालय नालासोपारा येथे लेखी स्वरूपात हरकत नोंदवावी अन्यथा करवसुलीच्या सोयीसाठी सदर हस्तांतरण करुन महानगरपालिका दपत्री याबाबतची नोंद घेतली जाईल.

| अ. क्र. | विभाग | मालमत्ता क्र. | रिसीट नं. | ज्याचे नावे मालमत्ता आहे त्याचे म्हणजे मालमत्ता विकणाऱ्या किंवा करदात्याचे नाव | खरीददाराचे किंवा अभिहस्तांकन करदात्याचे नाव |
|---------|-------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| १.      | गास-५ | GS०५/२२३३     | ३७४३६     | मुमताज अली शंख/मेहबुब अली शंख                                                  | जमीला अफरोज शंख                             |
| २.      | गास-५ | GS०५/३१६७/२१  | ३७५६९     | शिवधात्री अजय मिश्रा                                                           | मोह. रफिक मोह. उसमान मेमन यासमीन उसमान मेमन |
| ३.      | गास-५ | GS०५/१३७४     | ५१२४९     | नूरजहाँ मेहदीन शंख                                                             | करीमाबी गफ्फार शंख                          |
| ४.      | गास-५ | GS०५/३०१७/३६  | ४४८७७     | शेरबानो जब्बार सय्यद                                                           | हसीना फैयाज कुरेशी                          |
| ५.      | गास-५ | GS ०५/१०२५    | ५०२९५     | शंख महम्मद जफर                                                                 | असफिया मेहताब अहमद खान                      |
| ६.      | गास-५ | GS ०५/३०१७/५० | ४४८७९     | मो. अली गुलाम हुसेन माटी                                                       | मोह. उबेरा शराफतुल्ला शंख                   |
| ७.      | गास-४ | GS०४/१९८      | ४८६९९     | प्रभाकर विनायक गडकरी                                                           | शालन प्रभाकर गडकरी                          |
| ८.      | गास-५ | GS०५/१३३५     | ५०२९७     | अष्टभुजा डेव्ह.                                                                | विजय कुमार यादव                             |
| ९.      | गास-५ | GS०५/८३       | ४९७७४     | आजिम हुसेन खान                                                                 | शहनाझ इब्राहीम शंख                          |
| १०.     | गास-५ | GS०५/३१५६/३९  | ४५५८२     | एलिस जोसेफ आल्मेउ I                                                            | नेल्सन एलिस आल्मेडा                         |
| ११.     | गास-५ | GS०५/३१५६/११  | ४५५८३     | रजिया रियाज अहमद तडपत्री                                                       | रुखसाना अझिमूद्दीन सैय्यद                   |
| १२.     | गास-५ | GS०५/३१५३/३३  | ५०८५१     | मोहमद मोहशीनअली अन्सारी                                                        | मोहम्मद आजम शंख                             |
| १३.     | गास-५ | GS०५/३२१४/१४  | ५०५७४     | झरीना शंख                                                                      | फरहाना सद्दाम हुसेन शंख                     |
| १४.     | गास-५ | GS०५/३२३४/७   | ५१०८८     | फिरोज सिध्दीकी                                                                 | रामजतन गोपी गुप्ता                          |
| १५.     | गास-५ | GS०५/३०१६/२२  | ५१०११     | फातीमा रसूल                                                                    | तस्लीम फारुख शंख                            |
| १६.     | गास-५ | GS०५/३१११/१४  | ५०५८६     | कामरान नझीर शंख                                                                | सलमाबानो मोह. नजीर शंख                      |
| १७.     | गास-५ | GS०५/५१       | ५०३७९     | मुन्नालाल प्रजापती                                                             | कृपा शंकर                                   |
| १८.     | गास-४ | GS०५/१५७७     | ४८२९०     | व्हिक्टर सालू वाझ                                                              | अशीता सॅमसन वाझ                             |
| १९.     | गास-५ | GS०५/३१३६/४५  | ४३९८२     | समीना मोह. अयास मंसूरी                                                         | मंसूरी मोहम्मद अयास                         |
| २०.     | गास-५ | GS०५/३१३६/४५  | ४३९८२     | राजेश विश्वकर्मा                                                               | निर्मला जगत सिंह                            |

XXX

(बुधानी शेंठके)

प्र. कर अधिकार

प्रभाग समिती (ई) नालासोपारा

# महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के ऑनलाइन पोर्टल से छेड़छाड़, 22 विदेशी मेडिकल स्नातकों के पंजीकरण पर संदेह

**संवाददाता**  
मुंबई। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) में विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMG) के पंजीकरण के दौरान फर्जी दस्तावेजों के कथित इस्तेमाल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। परिषद की आंतरिक जांच में 22 संदिग्ध विदेशी मेडिकल स्नातकों के पंजीकरण से जुड़ी अनियमितताओं का पता चला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने महाराष्ट्र साइबर के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के अनुसार, परिषद की आंतरिक जांच और पंजीकरण अभिलेखों की छानबीन के दौरान यह अनियमितता सामने आई। प्रारंभिक जांच में 22 विदेशी मेडिकल स्नातकों के पंजीकरण संदिग्ध पाए गए। इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए गए। परिषद ने संबंधित व्यक्तियों को अपने मूल शैक्षणिक और पंजीकरण दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, ताकि दस्तावेजों की प्रामाणिकता और पंजीकरण की वैधता की जांच की जा सके। मामले की विस्तृत जांच के लिए महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने 14 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र साइबर के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई

**फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र साइबर ने शुरू की जांच, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी**



थी। परिषद के मुताबिक, जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और आगे की जांच जारी है। परिषद ने जांच एजेंसी को पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सा व्यवसाय में नैतिकता, कानूनी मानकों और डॉक्टरों के पंजीकरण की विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल पंजीकरण प्राप्त करने अथवा ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली से छेड़छाड़ करने जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिषद ने चेतावनी दी है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1965 और अन्य लागू कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिषद के अनुसार, मेडिकल पंजीकरण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य मरीजों

की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यह तय करना है कि महाराष्ट्र में केवल योग्य एवं विधिवत सत्यापित डॉक्टर ही चिकित्सा व्यवसाय करें। पंजीकरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता इस व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने नागरिकों से अपील की है कि वे उपचार कराने से पहले संबंधित डॉक्टर के पंजीकरण की पुष्टि परिषद की आधिकारिक वेबसाइट से करें। यदि किसी डॉक्टर के पंजीकरण या दस्तावेजों को लेकर संदिग्ध जानकारी सामने आती है, तो इसकी सूचना तत्काल परिषद को दें। फिलहाल 22 संदिग्ध पंजीकरणों की जांच जारी है। संबंधित व्यक्तियों की भूमिका, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और ऑनलाइन पोर्टल से छेड़छाड़ के पूरे मामले की वास्तविक स्थिति महाराष्ट्र साइबर की जांच के बाद स्पष्ट होगी।

# वसई क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का किया भंडाफोड़: 9 आरोपी गिरफ्तार

**संवाददाता**  
पालघर। मीरा-भायंदर, वसई-विरार (MBVV) पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट-2, वसई ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के एक कथित रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। कार्रवाई के दौरान करीब 9.86 लाख की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी 'रेड्डी बुक', 'रेड्डी 66' और 'नितिन ऑनलाइन बुक' जैसे ऑनलाइन पैनलों के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल और रम्मी समेत विभिन्न खेलों पर कथित रूप से सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग का संचालन कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि गिरोह के कुछ सदस्य गोवा में सक्रिय हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गोवा के परेनेम इलाके में कार्रवाई कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी भारत-पाकिस्तान

**गोवा में भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल पर लगा रहे थे सट्टा, 9.86 लाख की संपत्ति जब्त**



एशिया कप 2026 के फाइनल मैच पर सट्टा संचालित कर रहे थे। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इस तरह मामले में अब तक कुल नौ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 63 मोबाइल फोन, सात लैपटॉप, दो टैबलेट, एक राउटर, दो कैमरे, 70 सिम कार्ड, 58 एटीएम कार्ड तथा 89 पासबुक और

चेकबुक जब्त की हैं। पुलिस अब जब्त मोबाइल और डिजिटल उपकरणों की जांच कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क से कितने लोग जुड़े थे, ऑनलाइन लेनदेन का कुल आंकड़ा कितना है और सट्टेबाजी की रकम किन बैंक खातों के जरिए भेजी जा रही थी। क्राइम ब्रांच इस रैकेट के अन्य सदस्यों और इससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

# विश्व बेघर दिवस: मुंबई में बेघरों के अधिकारों की आवाज बुलंद अलग राज्यस्तरीय नीति बनाने की जोरदार मांग

**संवाददाता**  
मुंबई। विश्व बेघर दिवस के अवसर पर ताड़देव स्थित बॉटगार्ड लेन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में प्रसिद्ध सूचना अधिकार (RTI) कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार अनिल गलगली उपस्थित रहे। इस अवसर पर बेघर नागरिकों की समस्याओं, आश्रय केंद्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना तथा बेघरों के पुनर्वास के लिए अलग राज्यस्तरीय नीति बनाने की आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य आश्रय निगरानी समिति के अध्यक्ष उज्ज्वल उके और अनिल गलगली द्वारा बेघर नागरिकों के हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। अनिल गलगली ने पहचान फाउंडेशन के संस्थापक बृजेश आर्य और उनकी टीम के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्था लंबे समय से बेघर नागरिकों के उत्थान, पुनर्वास और सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रही है। झोपड़पट्टी पुनर्वास प्रधिकरण (SRA) और पक्के मकानों से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने आशवासन दिया कि संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए वे हर संभव सहयोग करेंगे। उन्होंने मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा संचालित आश्रय केंद्रों की जानकारी भी दी। गलगली ने कहा कि बेघर नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्थायी आवास मिलना आवश्यक



है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ इस विषय पर लगातार प्रयास और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना और SRA के माध्यम से अगले दो से तीन वर्षों में आवास के प्रश्न पर सकात्मक प्रगति होने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने सभी से पहचान फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करने की अपील की। पहचान फाउंडेशन के संस्थापक बृजेश आर्य ने बेघर नागरिकों के लिए अलग राज्यस्तरीय नीति बनाने की जोरदार मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए स्पष्ट और प्रभावी नीति नहीं बनेगी, तब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान मुश्किल है। ऐसी नीति से बेघर नागरिकों को आवास, पुनर्वास और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। आर्य ने बताया कि पहचान फाउंडेशन की टीम मतदान अधिकारियों और बृथ लेवल अधिकारियों (BLO) के साथ मिलकर मुंबई के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया

(Special Intensive Revision—SIR) में सहयोग कर रही है। संस्था का प्रयास है कि किसी भी पात्र भारतीय बेघर नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे। इसके लिए जनजागरण और लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने 'माय मुंबई फोटोग्राफी प्रोजेक्ट 2027' के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान बेघर महिलाओं ने भी बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं, अनुभव और विचार खुलकर साझा किए। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि बेघर नागरिकों को केवल अस्थायी आश्रय ही नहीं, बल्कि स्थायी घर, सामाजिक सम्मान और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं आभार प्रदर्शन पहचान फाउंडेशन के सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष रोकड़े ने किया। इस अवसर पर पहचान संस्था के सदस्य समीर वायकर, राज सिंह (SIP), बेला खरवा, कोकी, अनिता खरवा, सोनी वातन सहित अनेक बेघर नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

# एसटी की अतिरिक्त जमीनों का पीपीपी मॉडल पर होगा विकास: 98 साल तक लीज की अनुमति

**संवाददाता**  
मुंबई। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) के कब्जे वाली अतिरिक्त जमीनों का अधिकतम व्यावसायिक उपयोग कर महामंडल की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने एसटी की अतिरिक्त जमीनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर विकसित करने और इसके लिए 49+49 वर्ष यानी अधिकतम 98 वर्ष तक की लीज देने को मंजूरी दी है। इस फैसले से एसटी महामंडल की संपत्तियों के जरिए नियमित और दीर्घकालीन आय का नया स्रोत तैयार होने की उम्मीद है। विकास प्रक्रिया के संचालन और निगरानी के लिए परिवहन मंत्री एवं एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है।

राज्य सरकार का उद्देश्य एसटी की उपलब्ध जमीनों का योजनाबद्ध, पारदर्शी और व्यावसायिक उपयोग कर महामंडल की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। पीपीपी मॉडल के तहत निजी भागीदारों के माध्यम से इन जमीनों पर व्यावसायिक और अन्य उपयोगी परियोजनाएं विकसित की जा सकेंगी। शासन निर्णय के अनुसार, एसटी महामंडल की स्वामित्व वाली जमीन, भूमि अधिग्रहण के जरिए प्राप्त जमीन, पूर्व रोड ट्रांसपोर्ट विभाग से हस्तांतरित संपत्तियां, लीज पर मिली जमीन तथा उपहार पत्र के माध्यम से प्राप्त भूखंडों पर भी निर्धारित शर्तों के तहत पीपीपी परियोजनाएं लागू की जा सकेंगी। सरकार का मानना है कि लंबे समय तक उपयोग में नहीं आ रही अथवा अपनी पूरी व्यावसायिक क्षमता के अनुरूप इस्तेमाल नहीं हो रही जमीनों का विकास होने से महामंडल को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। साथ ही बस अड्डों और

**महामंडल की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का फैसला, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित**



संबंधित परिसरों में यात्री सुविधाओं तथा व्यावसायिक बुनियादी ढांचे के विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। नई नीति के तहत प्रत्येक भूखंड और परियोजना के लिए तय प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। उच्चस्तरीय समिति परियोजनाओं की व्यवहार्यता, आर्थिक लाभ और विकास से जुड़े विभिन्न

पहलुओं की समीक्षा करेगी। एसटी महामंडल की आर्थिक मजबूती के लिहाज से यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जमीनों के व्यावसायिक विकास से मिलने वाली दीर्घकालीन आय का उपयोग महामंडल की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा।

# वसई में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर VVMC की बड़ी कार्रवाई: करीब 3 टन माल जब्त

**संवाददाता**  
पालघर। वसई-विरार शहर महानगर पालिका (VVMC) ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री के खिलाफ शुक्रवार को वसई पूर्व के धूमल नगर इलाके में बड़ी कार्रवाई की। महानगरपालिका की टीम ने दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर करीब 3 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की और संबंधित व्यापारियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई नगर आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी., अतिरिक्त आयुक्त संजय हरवाड़े और उपायुक्त अर्चना दिवे के मार्गदर्शन में की गई। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, नोडल अधिकारी तथा वार्ड समिति क्रमांक-9 के अधिकारी अविनाश गुंजालकर के नेतृत्व में 17 सदस्यीय टीम ने अभियान चलाया। टीम में स्वास्थ्य निरीक्षक नितिन म्हात्रे, संदेश जाधव, यतिन डागे और आशीष पास्ते सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे।

महानगर पालिका की टीम ने धूमल नगर स्थित अंबिका एंटरप्राइजेज और चामुंडा स्टेशनरी एंड पैकेजिंग का निरीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार, दोनों स्थानों पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री मिली, जिसे जल कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब एक व्यापारी महानगरपालिका की कार्रवाई से नाराज होकर कथित तौर पर पेट्रोल से भरी बोतल ले आया। अधिकारियों के मुताबिक उसने दुकान में पेट्रोल डालते हुए कहा कि "बंबांद होने से बेहतर है कि दुकान जला दी जाए।" मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे रोक लिया और पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई। इसके बाद कुछ समय तक इलाके में तनाव का माहौल रहा, हालांकि महानगरपालिका की कार्रवाई जारी रखी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि

**धूमल नगर की दो दुकानों पर छापा, कार्रवाई से नाराज व्यापारी ने दुकान जलाने की दी धमकी, पुलिस को दी गई सूचना**



प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ जुर्माने के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महानगर पालिका ने यह भी

चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार धमकी, दबाव या अन्य तरीके से सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकती है।



संघातयाचा अमृत महोत्सव

समिती (H), विभागीय कार्यालय, नवघर माणिकपूर

एस. टी. डेपोजवळ, वसई रोड (प), ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ २०२.



दूरध्वनी :०२५० -२२३४२५८/२३३४३५४

Email :amch.vvmc@gov.com

जा. क्र.: व.वि.श.म./क.वि./एच/३२०६/२०२६-२७

दिनांक: ०८/१०/२०२६

जाहीर नोटीस

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४६९ ला अधिन राहुन या नोटीसीव्दारे वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील सर्व नागरीकांना सूचित करण्यांत येते की, खालील नमुद मिळकत धारकांनी मालमत्ता हस्तांतरण कामी लेखी अर्ज तसेच कागदपत्रे सादर केली आहेत. उक्त फेरफार प्रकरणी कोणतीही हरकत/तक्रार असल्यास त्यांनी कार्यालयात जाहीर नोटीस प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून सात (७) दिवसाच्या आत लेखी हरकत/तक्रार कागदपत्रांसह नोंदवावी सदर हरकत/तक्रार न आल्यास कार्यालय पुढील मालमत्ता हस्तांतरणाची कार्यवाही करण्यांत येईल.

| अ. क्र. | विभाग        | मालमत्ता क्र. | ज्याचे नावे मालमत्ता आहे त्याचे म्हणजेच विकणाऱ्या किंवा करदात्याचे नाव | खरेदीदाराचे किंवा अभिहस्तांकन करदात्याचे नाव  |
|---------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| १       | माणिकपूर १/१ | VN15/61156    | संकेत सायमन लोपीस                                                      | पेरुमलदास गणपती यादव व इतर १                  |
| २       | दिवाणमान ३   | VN24/6305     | मनोज यु शर्मा व आर्यन मनोज शर्मा                                       | विजय किशोरीलाल शर्मा                          |
| ३       | बन्हामपुर    | VN14/62452/35 | बी जे एन्टरप्राईजेस                                                    | शुभम रतनलाल नांबा                             |
| ४       | बन्हामपुर    | VN14/62451/12 | बी जे एन्टरप्राईजेस                                                    | ज्योती बाबू डॅनियल व जॅमसन जेम्स              |
| ५       | बन्हामपुर    | VN14/62451/6  | बी जे एन्टरप्राईजेस                                                    | रिचर्ड डिसिल्वा व प्राजक्ता रिचर्ड डिसिल्वा   |
| ६       | माणिकपूर २/१ | VN19/34694    | लुजान मॅथ्यु लोपीस                                                     | वॅलेरीयन मॅथ्यु लोपीस व रॉबिन्सन मॅथ्यु लोपीस |
| ७       | बन्हामपुर    | VN14/62235/10 | प्रभाकर गोपाल धरत                                                      | तनुजा मिलींद पाटील                            |
| ८       | दिवाणमान ४   | VN25/9678     | रज्जाक इमामुद्दीन मसुरी                                                | शमीम रज्जाक मन्सुरी                           |
| ९       | दिवाणमान ५/१ | VN26/8327     | अरविंद गेहलोत                                                          | भरतकुमार बगताजी प्रजापती                      |
| १०      | दिवाणमान ६/२ | VN29/15786    | हर्ष कुमार सहल                                                         | संदीप अविनाश धार्डे व निलम संदीप धार्डे       |
| ११      | चुळणा        | VN02/61891/48 | कोल एन्टरप्राईजेस                                                      | जर्चिता वाझ व क्लोफर्ड विनसेंट पॉल वाझ        |
| १२      | दिवाणमान ५/१ | VN26/11731    | जेम्स जॉन आल्मेडा                                                      | सुरीलकुमार नन्हेलाल गोंड व इतर १              |
| १३      | दिवाणमान ८   | VN31/19202    | एल एल सायमन                                                            | सुनिल जमादार खलाटे                            |
| १४      | उमळमान       | VN01/56327    | संदीप मधुकर नवल व इतर १                                                | कमल कैलाश कोठारे व साधना कोठारे               |
| १५      | माणिकपूर २/१ | VN19/35474    | इजाबेल पास्कोल पिंटो                                                   | इजाबेल पास्कोल पिंटो व जोनस पास्कोल पिंटो     |
| १६      | उमळमान       | VN01/59396    | क्लेमेंट विल्सन डिसोजा                                                 | सुराती रंगलाल यादव                            |
| १७      | नवघर ४/३     | VN11/3920     | हिना जिनेश शाह                                                         | कालेलकर सर्जिकल इंडस्ट्रीस                    |
| १८      | दिवाणमान ७   | VN30/18132    | शशांक कुमार व आदित्य अशोक कुमार                                        | कृष्णा अशोक कुमार                             |
| १९      | चुळणा        | VN02/57751    | जेनीफर मेरी नईलर                                                       | दिप्ती विजय शाह                               |
| २०      | माणिकपूर १/२ | VN16/62387/24 | उत्तरा एस अभ्यंकर व अभ्यंकर संजीव                                      | ऑलवेन वन्हर्ड डिसोजा                          |



जि. पावघर

(जोसेफ मिनेजीस)  
कर अधिक्षक  
प्रभाग समिती "एच"  
वसई विरार शहर महानगरपालिका

## नाना पाटेकर के निधन से भावुक हुई हेमा मालिनी बोलीं- उनका आखिरी फोन आया था, लेकिन बात नहीं हो सकी

**संवाददाता**  
**मुंबई।** हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है। 75 वर्षीय अभिनेता का 8 अक्टूबर को गोवा में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से अभिनेत्री एवं सांसद हेमा मालिनी भी गहरे सदमे में हैं। उन्होंने नाना पाटेकर को याद करते हुए एक भावुक खुलासा किया कि निधन से कुछ दिन पहले अभिनेता ने उन्हें फोन किया था, लेकिन यात्रा के दौरान व्यस्त होने के कारण वह उनसे बात नहीं कर सकीं। हेमा मालिनी ने एक बातचीत में बताया कि कुछ दिन पहले नाना पाटेकर का फोन आया था और उनकी बातचीत भी हुई थी। इसके बाद करीब एक सप्ताह पहले फिर उनका फोन आया, लेकिन उस समय वह यात्रा कर रही थीं, इसलिए बातचीत नहीं हो पाई। हेमा मालिनी ने कहा- कुछ दिन पहले उनका फोन आया था और हमने बात की थी। लगभग एक सप्ताह पहले भी उनका फोन आया था, लेकिन मैं यात्रा कर रही थी, इसलिए बात नहीं हो सकी। जब आज उनके निधन की खबर सुनी तो मैं स्तब्ध रह गई। हेमा मालिनी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अभिनेता की असाधारण अभिनय प्रतिभा, हिंदी और मराठी फिल्मों में उनके योगदान तथा सामाजिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि

फिल्म उद्योग ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया है, जिन्होंने अपनी विशिष्ट अभिनय शैली से अलग पहचान बनाई और जिन्हें अभिनय की एक संस्था माना जाता था। हेमा मालिनी ने विशेष रूप से नाम फाउंडेशन के माध्यम से किसानों और वंचित समुदायों की सहायता के लिए किए गए नाना पाटेकर के कार्यों को याद किया। उन्होंने कहा कि नाना ने अभिनय के साथ समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए भी निरंतर काम किया। अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें नाना पाटेकर की फिल्में और अलग-अलग किरदार निभाने का उनका अनोखा अंदाज बेहद पसंद था। उन्होंने यह भी याद किया कि नाना पाटेकर ने कभी उन्हें क्लासिक सिनेमा की अपनी पसंदीदा अभिनेत्री बताया था। हेमा मालिनी के अनुसार, नाना पाटेकर ने हिंदी और मराठी सिनेमा में ऐसी विरासत छोड़ी है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। फिल्म उद्योग को उनकी कमी हमेशा महसूस होगी।

**गोवा में कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन**  
नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर की सुबह गोवा के डोना पाउला स्थित आवास पर तबीयत बिगड़ने के बाद निधन हो गया। उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुबह करीब 5:20 बजे मृत घोषित कर दिया। उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने निधन की जानकारी दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार्डियक अरेस्ट को मौत का कारण

**75 वर्ष की उम्र में दिग्गज अभिनेता का निधन, हेमा मालिनी ने कहा— हिंदी और मराठी सिनेमा ने खो दिया एक अनमोल कलाकार**



बताया गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे के निकट डोंगजे स्थित फार्महाउस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बेटे मल्हार पाटेकर ने अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं।

**दमदार अभिनय और यादगार संवादों से बनाई अलग पहचान**  
1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र में जन्मे नाना पाटेकर ने वर्ष 1978 में फिल्म ‘गमन’ से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। अपने प्रभावशाली अभिनय, विशिष्ट संवाद अदायगी और जटिल किरदारों को जीवंत करने की क्षमता के कारण उन्होंने फिल्म उद्योग में अलग पहचान बनाई। अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने ‘परिदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘वजूद’, ‘यशवंत’, ‘अब तक छपन’, ‘अपहरण’, ‘टैक्सी नंबर 9211’ और मराठी फिल्म

‘नटसम्राट’ जैसी अनेक यादगार फिल्मों में अभिनय किया। गंभीर भूमिकाओं के साथ हास्य अभिनय में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। फिल्म ‘वेलकम’ और ‘वेलकम बैक’ में गैस्टर उदय शेठ्ठी का उनका किरदार दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने अभिनय के साथ सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से किसानों की सहायता के लिए नाम फाउंडेशन के माध्यम से किए गए उनके प्रयासों को याद किया जा रहा है। नाना पाटेकर के निधन से भारतीय सिनेमा ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया, जिन्होंने अपने अभिनय, स्पष्टवादी व्यक्तित्व और सामाजिक सरोकारों से दर्शकों के दिलों में स्थायी स्थान बनाया।

## ‘तुम्बाड 2’ में आलिया भट्ट की एंट्री सिर्फ दो मुलाकातों में हुई फिल्म के लिए तैयार

**संवाददाता**  
**मुंबई।** साल 2018 में रिलीज हुई चर्चित हॉरर फिल्म ‘तुम्बाड’ के सीक्वल ‘तुम्बाड 2’ को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। फिल्म में अभिनेता और निर्माता सोहम शाह एक बार फिर विनायक राव के किरदार में दिखाई देंगे। वहीं, आलिया भट्ट और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नए किरदारों में नजर आएंगे। इस बीच सोहम शाह ने आलिया भट्ट की कार्टिंग को लेकर दिलचस्प खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आलिया को फिल्म के लिए राजी करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और महज दो मुलाकातों में उनकी कास्टिंग तय हो गई। एक इंटरव्यू के दौरान सोहम शाह ने बताया कि फिल्म की टीम ने आलिया भट्ट को कहानी सुनाई थी। इसके बाद अभिनेत्री ने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिल्म में काम करने के लिए सहमति दे दी। सोहम के अनुसार, आलिया को फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई और पूरी प्रक्रिया काफी सहज रही। सोहम शाह ने कहा- हमने उन्हें कहानी सुनाई और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी। इसके बाद उन्होंने तुरंत हां कह दिया। उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। वह बेहद

ईमानदार और प्रोफेशनल हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया काफी आसान रही। सोहम ने आलिया भट्ट की अभिनय क्षमता के साथ उनकी व्यावसायिक समझ की भी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि पहली मुलाकात में ही आलिया ने फिल्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे, जिससे उनकी समझ और काम के प्रति गंभीरता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि आलिया जितनी बेहतरीन अभिनेत्री हैं, उनकी व्यावसायिक समझ भी उतनी ही अच्छी है। पहली मुलाकात में कहानी सुनने के बाद उन्होंने दो से तीन दिनों के भीतर पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली। इसके बाद दूसरी मुलाकात हुई और फिल्म के लिए उनकी सहमति मिल गई। सोहम के मुताबिक, “किसी बड़े कलाकार को केवल दो मुलाकातों में फिल्म के लिए तैयार कर लेना आम बात नहीं है। आलिया ने कहानी की खूबियों को तुरंत समझ लिया। वह बेहद तेज और समझदार हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि आलिया भट्ट ने ‘तुम्बाड’ का पहला भाग देखा था और उन्हें वह काफी पसंद आया था। हालांकि, सोहम ने सीक्वल में आलिया के किरदार से जुड़ी अधिक



जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म में आलिया का किरदार बेहद महत्वपूर्ण होगा और कहानी को आगे बढ़ाने में उसकी बड़ी भूमिका रहेगी। सोहम ने विश्वास जताया कि फिल्म देखने के बाद दर्शक खुद समझ जाएंगे कि आलिया को इस भूमिका के लिए चुनना कितना सही फैसला था। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में रिलीज हुई ‘तुम्बाड’ हिंदी पीरियड हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन राही अनिल बर्वे ने किया था। फिल्म में आनंद गांधी ने रचनात्मक निदेशक और आदेश प्रसाद ने सह-इसकी कहानी मितेश शाह, आदेश

प्रसाद, राही अनिल बर्वे और आनंद गांधी ने लिखी थी। फिल्म का निर्माण सोहम शाह, आनंद एल. राय, मुकेश शाह और अमिता शाह ने किया था। इसमें सोहम शाह ने विनायक राव की मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म की कहानी ब्रिटिश शासनकाल के भारत में स्थित तुम्बाड गांव के एक रहस्यमयी खजाने और उससे जुड़े लालच के इर्द-गिर्द घूमती है। अब ‘तुम्बाड 2’ में नए कलाकारों के जुड़ने और कहानी के विस्तार को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। खासकर आलिया भट्ट और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदारों को लेकर फिल्म प्रेमियों में दिलचस्पी बनी हुई है।

व्यावसायिक इस्तेमाल होने से उन्हें ऐसी क्षति पहुंच सकती है, जिसकी भरपाई करना कठिन होगा। अदालत ने यह भी माना था कि इस प्रकार की गतिविधियों से अभिनेता की प्रतिष्ठा प्रभावित होने की आशंका है। अदालत ने प्रथम दृष्टया अमिताभ बच्चन के पक्ष में मामला पाते हुए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। इस आदेश का उद्देश्य अभिनेता के नाम, आवाज, तस्वीर और अन्य व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाना था। अब इस मामले में कुछ प्रतिवादियों के साथ समझौता होने की जानकारी सामने आने के बाद अदालत ने शेष विवादों को सुलझाने के लिए समय दिया है। हालांकि, यदि समझौता पूरा नहीं होता और अमिताभ बच्चन मुकदमा जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें अदालत के निर्देशानुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। इस बीच अमिताभ बच्चन टेलीविजन के लोकप्रिय विक्व शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के 18वें सीजन में वापस होना दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। इस सीजन की थीम ‘सोचना पड़ेगा’ रखी गई है, जिसमें प्रतिभागियों के सामान्य ज्ञान के साथ उनकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता पर भी जोर दिया जा रहा है। फिल्मों की बात करें तो अमिताभ बच्चन निर्देशक नाग अश्विन की फिल्म ‘कल्कि 2898 AD: पार्ट 2’ में एक बार फिर अश्वत्थामा के किरदार में नजर आने वाले हैं।

## पार्टी के लिए बोझ बना तो बिना पलक झपकाए घर बैठ जाऊंगा, लेकिन टूटूंगा नहीं: हरीश रावत

**संवाददाता**  
देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा, नेतृत्व में विश्वास और राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता और यदि कभी उन्हें लगेगा कि वह कांग्रेस के लिए बोझ बन रहे हैं या पार्टी नेतृत्व उन्हें घर बैठने का निर्देश देगा, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पालन करेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों और उनके योगदान का सही आकलन किया जाना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर साझा एक विस्तृत पोस्ट में हरीश रावत ने कहा- यह शाश्वत सत्य है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता और नेतृत्व के प्रति आस्था लोकतंत्र को शक्ति देती है। मैंने हमेशा पार्टी को बड़ा माना है और नेतृत्व के प्रति अटूट आस्था रखी है। रावत ने अपने राजनीतिक जीवन की कठिन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2002 और 2012 जैसी कठिन परीक्षा उनके सामने दोबारा नहीं आ सकती। उन परिस्थितियों में भी वह हार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहे और पार्टी का झंडा ऊंचा रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनकी निष्ठा और योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। हरीश रावत ने कहा- हमारा लक्ष्य पार्टी हित होना चाहिए। मैं अपने पत्रकार मित्रों और राजनीतिक साथियों को स्पष्ट कर



देना चाहता हूं कि जिस क्षण मुझे लगेगा कि मैं पार्टी के लिए बोझ बन रहा हूं या मुझसे कहा जाएगा कि आप घर बैठिए, मैं बिना पलक झपकाए उस आदेश का पालन करूंगा। हालांकि, उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि उनके राजनीतिक योगदान और वर्तमान परिस्थितियों का सही आकलन कौन करेगा। रावत ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह स्वयं कोई फैसला ले लें और बाद में कुछ लोग यह कहने लगे कि उनके फैसले से कांग्रेस की संभावनाएं कमजोर हो गईं। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आज भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता का समर्थन उनके साथ मजबूती से खड़ा है। चुनावी हार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब चुनावी पराजय के पीछे के कारण भी सामने आने लगे हैं और मतदाता खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वह लालकुआं और किच्छा क्षेत्र में गए थे, जहां कई लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें आज भी आश्चर्य है कि वह चुनाव कैसे हार गए। रावत ने अपनी उत्तराखंडी पहचान पर गर्व व्यक्त करते हुए

कहा कि वह विशुद्ध रूप से उत्तराखंडी, गढ़वाली और कुमाऊंकी हैं। उन्होंने कहा- लुढ़कते-लुढ़कते, धिसते-धिसते शून्य में मिल सकता हूं, लेकिन टूट नहीं सकता। भाजपा पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने आरोप लगाया कि उनके पीछे सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगाया गया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि राज्य के अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि उन्हें ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। रावत ने दावा किया कि इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा आज भी उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उनकी छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार प्रयास कर रही है। रावत के अनुसार, उन्हें ट्रोल करने और उनकी छवि बिगाड़ने के लिए भाजपा ने विशेष रूप से कई पेज समर्पित कर रखे हैं। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने पोस्ट में कोई स्वतंत्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। कांग्रेस के भीतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की ओर संकेत करते हुए रावत ने कहा कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि जिन लोगों से उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, वे भी उनसे मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रूप से उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वह अब ऐसी प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठ चुके हैं। हरीश रावत ने कहा- मैं सबके लिए एक पूरक हूं।

## उन्नाव में वृहद रोजगार मेला, 580 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट

**20 से अधिक कंपनियों ने दिए 2,000 से ज्यादा रोजगार अवसर, चयनित युवाओं को मंच से मिले ऑफर लेटर**



सॉल्यूशंस और एल एंड टी कंस्ट्रक्शन स्क्रिपल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समेत कई कंपनियों ने भाग लिया। सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रिशियन, सुपरवाइजर, सेल्स एवं मार्केटिंग, फील्ड ऑफिसर, स्कैफोल्डर और वैन डिलीवरी एंजीक्यूटिव सहित विभिन्न पदों पर अवसर उपलब्ध कराए गए। इस दौरान अग्निवीर योजना, मुख्यमंत्री युवा भारतीय वायुसेना जानकर चुकरी एयरमैन सिलेक्शन टीम, एलआईसी, काउंसिल फॉर लेटर एक्सप्लोटर्स, जी०एएस सिक्योर

कुमार, आकाश, प्रभाकर गुप्ता, शोभित, मनीष और हर्षित को मंच से ऑफर लेटर प्रदान किए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हेमेंद्र सिंह सेगर ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार और व्यावसायिक अवसरों से जोड़ना भी है। कार्यक्रम का संचालन अनुपम सिंह ने किया। आयोजन में करियर काउंसिलिंग सेल के समन्वयक डॉ. अनिल साहू सहित कॉलेज और सेवायोजन कार्यालय के कर्मचारियों ने सहयोग किया।

## यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध चुनाव भाजपा के 8 और सपा के 2 उम्मीदवार जीते



**संवाददाता**  
**लखनऊ, उत्तर प्रदेश।** उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। नामांकन वापसी की समयसीमा पूरी होने के बाद भाजपा के आठ और समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन भी जांच में खारिज हो जाने के बाद 10 सीटों के लिए केवल 10 वैध उम्मीदवार ही बचे थे, इसलिए 16 अक्टूबर को प्रस्तावित मतदान की आवश्यकता नहीं रही। भाजपा की ओर से धर्मपाल सिंह, प्रकाश पाल, श्रुति गंगवार, विद्यासागर सोनकर, प्रियंका सिंह रावत, राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडेय और राम प्रताप सिंह चौहान दो निर्वाचित हुए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव और उद्योग जगत से जुड़े धनराज परिमल नयथानी राज्यसभा पहुंचे हैं। इन 10 सीटों

पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होना है। इससे पहले इनमें आठ सीटें भाजपा, एक सपा और एक बसपा के पास थीं। नए परिणाम के बाद भाजपा के पास आठ और सपा के दो सीटें होंगी, जबकि उत्तर प्रदेश से बसपा का राज्यसभा प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है। रिटर्निंग अधिकारी ने सभी जांच में खारिज हो जाने के बाद 10 सीटों के लिए केवल 10 वैध उम्मीदवार ही बचे थे, इसलिए 16 अक्टूबर को प्रस्तावित मतदान की आवश्यकता नहीं रही। भाजपा की ओर से धर्मपाल सिंह, प्रकाश पाल, श्रुति गंगवार, विद्यासागर सोनकर, प्रियंका सिंह रावत, राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडेय और राम प्रताप सिंह चौहान दो निर्वाचित हुए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव और उद्योग जगत से जुड़े धनराज परिमल नयथानी राज्यसभा पहुंचे हैं। इन 10 सीटों

## मछली पकड़ने गए तीन लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

**संवाददाता**  
**चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।** चित्रकूट जिले में मानिकपुर थाना क्षेत्र के हेला गांव में शनिवार सुबह बंधा तालाब के जडैया में मछली पकड़ने गए तीन लोगों की मौत हो गई। सुबह की घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों की पहचान राजपाल (17) पुत्र स्व. लवकुश निवासी हेला, महेंद्र (30) पुत्र जोधी निवासी हेला और रामकेश (32) पुत्र तीर्थ निवासी चुरेहकसरवा के रूप में हुई है। बताया गया कि तीनों के साथ महेंद्र का भाई सुरविजय भी गया था। उसी ने घर पहुंचकर घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। तीनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। एक साथ तीन मौतों से गांव में मातम छा गया है। इसको को पोस्टमॉर्टम की जांच भेजा गया है। इस हादसे में 17 वर्षीय राजपाल की मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता का साथी पहले ही उठ चुका था और अब राजपाल की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।